

प्राक्कथन

भारत में डेढ़ दशक से थोड़े अधिक समय से व्यापक आर्थिक सुधार का कार्य चल रहा है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि की पूर्ण संभाव्यता का दोहन करना इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य है। वित्तीय संसाधनों की बेहतर बिचवई के जरिए अर्थव्यवस्था में समग्र दक्षता प्राप्त करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दक्षतापूर्वक कार्य किया जाना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, बैंकिंग क्षेत्र में सतत आधार पर व्यापक सुधार शुरू किए गए हैं, ताकि एक दक्ष, सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी तथा गतिशील बैंकिंग क्षेत्र का निर्माण किया जा सके। उक्त सुधारों में ब्याज दरों को विनियमित करने, बाह्य अवरोध हटाने, विनियमन तथा पर्यवेक्षण में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने, निजी क्षेत्र के नए बैंकों एवं विदेशी बैंकों के जरिए प्रतिस्पर्धा शुरू करने तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन और कार्यपरक स्वायत्तता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुल मिलाकर, बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है परंतु अब इसके सामने कई नयी चुनौतियां हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि के उच्च पथ पर अग्रसर है तथा वृद्धि की प्रक्रिया बनाए रखने में बैंकिंग क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। बासेल II, जो मार्च 2009 के अंत से पूर्णतः लागू हो जाएगा, न सिर्फ कार्यान्वयन के रूप में अपितु पूंजी जुटाने के रूप में भी कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। भारत क्रमिक रूप से पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर अग्रसर है, जिससे कई विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। बैंकों का परिचालनात्मक माहौल बदल गया है, जिसके फलस्वरूप बैंक अधिकाधिक विशाखीकृत हो रहे हैं। कई वित्तीय संगठनों का भी उदय हुआ है, जिससे उपयुक्त विनियामक व्यवस्थाएं जरूरी हो गई हैं। प्रौद्योगिकी से जटिल वित्तीय उत्पादों का नवोन्मेष हुआ है, जिससे विनियामकों के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। अतः भारत में बैंकिंग परिचालनों के विभिन्न पहलुओं का गंभीर विश्लेषण उपयुक्त होगा ताकि उनकी शक्तियों और कमजोरियों का, बैंकिंग क्षेत्र के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों का तथा उनसे निपटने के लिए आवश्यक उपायों का आकलन किया जा सके।

केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सामयिक सुसंगतिवाले मुद्दों का विवेचनात्मक विश्लेषण करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक के आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग ने वर्ष 1998-99 से मूल विषय (थीम) आधारित **मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट** शुरू की। अब तक, आठ रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं, जिनमें केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित रिपोर्टों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें 2003-04 की रिपोर्ट में **मौद्रिक नीति के विकास**, 2004-05 की रिपोर्ट में **भारत में केंद्रीय बैंकिंग के विकास** तथा 2005-06 में **वित्तीय बाजारों के विकास तथा केंद्रीय बैंक की भूमिका** का ब्यौरेवार विश्लेषण किया गया है। इन रिपोर्टों के साथ, यह रिपोर्ट रिजर्व बैंक के अधिकांश कार्यों को समाविष्ट कर लेती है। इस वर्ष की रिपोर्ट का मूल विषय **‘‘भारत में बैंकिंग क्षेत्र : उभरते मुद्दे तथा चुनौतियां’’** है। इस रिपोर्ट में बैंकिंग क्षेत्र के सामने मौजूद विभिन्न वर्तमान तथा उभरती चुनौतियों का उल्लेख करने और उनके समाधान के उपाय सुझाने पर जोर दिया गया है। जहां कहीं संभव हुआ, इस रिपोर्ट में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन/की प्रथाओं की तुलना अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से की गई है। इस रिपोर्ट में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, हालांकि बैंकिंग क्षेत्र के अन्य खंडों यथा शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में भी, जहां कहीं उपयुक्त लगा और जहां कहीं सुसंगत आंकड़े उपलब्ध थे, चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट के परिमाण तथा इसकी व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए, मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट का यह संस्करण 2006-08 की अवधि के लिए है तथा इसे दो खंडों अर्थात् खंड I (अध्याय I से V) और खंड II (अध्याय VI से XI) में जारी किया जा रहा है।

यह रिपोर्ट परिचालनात्मक विभागों के सक्रिय सहयोग से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग में तैयार की गई है। डॉ. जनक राज, परामर्शदाता, ने डॉ. जी.एस.भाटी, तत्कालीन प्रधान परामर्शदाता के समग्र पर्यवेक्षण के तहत, इस रिपोर्ट के संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण और समन्वय किया।

इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने संबंधी मुख्य दल में आशा पी. कन्नन, निशिता राजे, राजन गोयल, मुनीष कपूर, धृतिद्युति बोस, कुमुदिनी हाजरा, जे.के.खुन्द्रकपम, रेखा मिश्रा, अनुपम प्रकाश, पी.के.पांडा, अनुपम सोनल, ए.करुणागरन, अभिमान दास, भुपाल सिंह, सुनील कुमार, जे.बी.सिंह, पीएसएस विद्यासागर, राजीव जैन, राजमल, जय चंदर, पंकज सेटिया, जी.जेयाकुमार, प्रभात गुप्ता, आर.शुक्ला, जे.बनार्ड, आर.सुदीप, आशीष कुमार वर्मा, कुमारजीत मंडल, दिपांकर मित्रा, स्नेहल हेरवाडकर, विनोद बी.भोई, एस.चिन्नगैहलियन, अरुण विष्णु कुमार, समीर आर बेहरा, ए.एन.यादव, अवधेश शुक्ला, आशीष थॉमस जॉर्ज, राखी पी.बी., थांगजसन सोन्ना, राकेश कुमार, इंद्राणी मन्ना, सुभजित राय तथा अभिलाषा शामिल थे।

उक्त दल को वी.लीलाधर, श्यामला गोपीनाथ, उषा थोरात तथा के.कनगसभापति से प्राप्त उल्लेखनीय सुझावों से लाभ मिला।

परिचालनात्मक विभागों अर्थात् बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, मौद्रिक नीति विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, शहरी बैंक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने अत्यधिक सराहनीय अंशदान किया।

मैं आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के अधिकारियों के व्यावसायिक कौशल और परम निष्ठा की अत्यधिक सराहना करता हूँ, जिसके बिना इस रिपोर्ट को प्रकाशित करना संभव नहीं हो पाता।

राकेश मोहन
उप गवर्नर